



लोक सभा सचिवालय

प्रेस एवं जन सम्पर्क स्कंध

संसद भवन, नई दिल्ली

**LOK SABHA SECRETARIAT**

Press and Public Relations Wing

Parliament House, New Delhi

## प्रेस विज्ञप्ति PRESS RELEASE

“न्यायसंगत, शांतिपूर्ण तथा समृद्ध विश्व के लिए सुस्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जरूरी है” - लोक सभा अध्यक्ष

कैंप बेलग्रेड, 14 अक्टूबर 2019 : लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला जो इस समय बेलग्रेड (सर्बिया) में अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, ने आज अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सुदृढीकरण : संसद की भूमिका और तंत्र तथा क्षेत्रीय सहयोग का योगदान' विषय पर सभा को सम्बोधित किया।

प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि न्यायसंगत, शांतिपूर्ण तथा समृद्ध विश्व के लिए एक संतुलित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का होना अनिवार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके लिए, ऐसे मानदंड और मानक तैयार किए जाने की आवश्यकता है, जो सम्पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वीकार्य हों। यह यह विचार व्यक्त करते हुए कि आपसी निर्भरता को समझ कर ही आज विश्व के राष्ट्र राज्य एक मंच पर आने के लिए इच्छुक हैं, श्री बिरला ने कहा कि इसी कारण वे आपसी रिश्तों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कानून के शासन को महत्व दे रहे हैं। व्यापार, निवेश और बौद्धिक संपदा, परिवहन और संचार; समुद्र एवं महासागर जैसे विश्व के साझे संसाधनों के मामले में इस सिद्धांत को अपनाया जा रहा है। इसके अलावा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आदि जैसे व्यापक क्षेत्रों में भी कानून बनाने के लिए प्रयास किये जा रहा हैं ।

श्री बिरला ने खेद व्यक्त किया कि कई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं, जिनके संबंध में हम गंभीर और सामूहिक रूप से क्षति पहुंचाने वाले मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून विकसित नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद ऐसा ही एक गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए आज आतंकवाद के मामले में प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है । उन्होंने कहा कि संकीर्ण भूराजनैतिक हितों के कारण इस मुद्दे पर अभी तक प्रभावी वैश्विक कानून नहीं बनाया जा सका है। विडम्बना यह है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रभावी कानून बनाने की दिशा में होने वाली प्रगति को रोकने के लिए कई देश विभिन्न अप्रासंगिक कानूनी विचारधाराओं का सहारा लेते रहते हैं ।

लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत का विश्वास है कि आज के परस्पर निर्भरता वाले विश्व में हम ऐसी अनेक साझा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनका समाधान सहकारी और प्रभावी बहुपक्षीय सहयोग के जरिये ही किया जा सकता है।

यह विचार व्यक्त करते हुए कि विदेश नीति, सामान्य रूप से कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में आती है, श्री बिरला ने कहा कि जब तक संसद प्रभावी कानून नहीं बनाती है तब तक अन्तर्राष्ट्रीय संधियों, अभिसमयों (conventions) और समझौतों से जुड़े दायित्वों को कानून की किताबों में सम्मिलित नहीं किया जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद का यह दायित्व है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कानून बनाने में रचनात्मक भूमिका निभाए।

लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि सांसदों के वैश्विक संगठन के रूप में अन्तर-संसदीय संघ, विश्व के सामने मौजूद मुख्य मुद्दों के संबंध में 'विश्वव्यापी संसदीय चर्चा हेतु केन्द्र बिन्दु' बन गया है और अंतर-संसदीय संघ देशों के बीच 'शांति और सहयोग' तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना और मजबूती के लिए निरन्तर काम कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अन्तर-संसदीय संघ की सभाओं में व्यापक विचार-विमर्श के लिए उठाए गए मुद्दों के जरिए सांसदगण बहुत कुछ सीखते हैं। साथ ही विभिन्न देशों की संसद अन्तर-संसदीय संघ द्वारा तय किए गए एजेंडे का अनुपालन करते हुए एक सुविचारित जनमत तैयार करती हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अंतर-संसदीय संघ 21वीं शताब्दी की उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए लोकतंत्र, सुशासन, शांति और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखेगा।

## **A WELL DEFINED INTERNATIONAL ORDER IS IMPERATIVE FOR A JUST, PEACEFUL AND PROSPEROUS WORLD – LOK SABHA SPEAKER**

**Camp Belgrade, 14 October 2019 :** Lok Sabha Speaker, Shri Om Birla, who is leading an Indian Parliamentary Delegation (IPD) to the 141<sup>st</sup> Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU) in Belgrade (Serbia) addressed the Assembly on the theme 'Strengthening International Law: Parliamentary roles and mechanisms and the contribution of Regional Cooperation' today.

Addressing the delegates, Shri Birla said that a well-defined international order is imperative for a just, peaceful and prosperous world. He emphasised that this required laying down norms and standards acceptable to the entire international community. Observing that the Comity of States is willing to share a common platform as it is aware of inter-dependence of nations, Shri Birla said that the emphasis is being laid on the rule of law in a wide range of areas in order to promote transparency in mutual relations. This principle is being followed in the areas of trade, investment and intellectual property; transport and communication; use of global commons such as seas and oceans, environment, climate change etc. Besides, the Rule of Law is being upheld in the areas of Environment and Climate Change etc.

Shri Birla stated that there are still some areas where we have not been able to develop international rule of law to our collective disadvantage. He said that terrorism is one such alarming concern. Hence, effective international collaboration is required to tackle terrorism. He also said that law making on this issue continues to falter in view of narrow geopolitical interests. Ironically, often States hide behind legal concepts designed for different contexts to stop progress on this vital issue.

Lok Sabha Speaker said that India strongly believes that cooperative and effective multilateralism is the only answer to the range of inter-connected challenges that we face in our inter-dependent world.

Expressing the view that the foreign policy has been the domain of the Executive, Shri Birla said that unless Parliament enacts the enabling legislation, the obligations arising from international treaties, conventions and agreements do not gain a place in the statute book. He emphasised that the Parliament has a responsibility to play a constructive role in passing the necessary legislations to give effect to international commitments.

Lok Sabha Speaker further said that IPU, as the world organization of Parliaments, has become the “focal point for worldwide parliamentary dialogue” on key issues confronting the globe and it has been working for peace and cooperation among nations and for the firm establishment of democratic institutions. He observed that the issues taken up for comprehensive deliberation in IPU Assemblies are vital learning experiences for parliamentarians. Besides the agenda set by the IPU is pursued by national Parliaments to create an informed public opinion. He also expressed the view that IPU would continue to contribute significantly towards promoting democracy, good governance, peace and progress to meet the emerging global challenges of the 21<sup>st</sup> Century.